भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5074

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

5074. श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री विजय बघेल:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री मनोज तिवारी:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री सुधीर गुप्ता:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री नलिन सोरेन:
श्री जुगल किशोर:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
डॉ. भोला सिंह:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री नव चरण माझी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

श्री विष्णु दयाल राम:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री गोडम नागेश:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री भोजराज नाग:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री सतीश कुमार गौतम:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के प्रारंभ से लेकर अब तक कर्नाटक और दक्षिण कन्नड़ जिले, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर सहित राज्यवार, जिलावार और चरण-वार कितने गांवों को गोद लिया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आदर्श गांवों के रूप में विकसित की गई ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है और "मॉडल" स्थिति का आकलन करने के लिए उपरोक्त स्थानों सहित राज्यवार और जिला-वार क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन जैसी योजना के अंतर्गत अवसंरचना, सामाजिक संकेतकों, आजीविका सृजन और परिणामों के संदर्भ में एसएजीवाई परिणामों का राज्य-वार कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थानों सहित तत्संबंधी मूल्यांकन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'रूर्बन' (ग्रामीण-शहरी) मिशन के अंतर्गत चरण-I और चरण-II में अनुमोदित समूहों का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल की गई ग्राम पंचायतों और गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(च) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) और जल जीवन मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं में राज्य-वार और जिला-वार कितने प्रतिशत गोद लिए गए गांवों ने संतृप्ति प्राप्त की है;

(छ) क्या मंत्रालय की सभी फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों को सार्वभौमिक रूप से संतृप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार समय-सीमा क्या है; और

(ज) क्या बुलंदशहर जिले के किन्हीं गांवों को एसएजीवाई के अंतर्गत गोद लिया गया है और यदि हां, तो उनमें विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) माननीय संसद सदस्यों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत 3,361 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। एसएजीवाई के तहत चयनित राज्य-वार और चरण-वार ग्राम पंचायतों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया हैं।

(ख) चिह्नित ग्राम पंचायत (जीपी) को आदर्श ग्राम में परिवर्तित करने हेतु, जनता द्वारा प्राथमिकता दी गई आवश्यकताओं के आधार पर एक कार्य समूह द्वारा ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार की जाती है। ग्राम विकास योजना के अंतर्गत नियोजित सभी परियोजनाओं/गतिविधियों के पूर्ण होने पर ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम माना जाता है। एसएजीवाई के तहत गोद ली गई कुल 1868 ग्राम पंचायतों ने अपनी वीडीपी के अंतर्गत नियोजित 100% परियोजनाओं/गतिविधियों को पूरा कर लिया है।

(ग) और (घ) एसएजीवाई के अंतर्गत, वीडीपी के तहत नियोजित परियोजनाओं और गतिविधियों का निर्णय कार्य समूह द्वारा लिया जाता है, ग्राम सभा द्वारा इसे पारित किया जाता है और जिला स्तरीय समिति द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। इस मंत्रालय ने जनसंख्या के सभी वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता के उन्नयन में इस कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने हेतु, एसएजीवाई और गैर-एसएजीवाई ग्राम पंचायतों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित किया है। हालाँकि, राज्य-वार मूल्यांकन को इस अध्ययन के कार्य-क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।

(ङ) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूर्बन क्लस्टर बनाना है। एसपीएमआरएम के अंतर्गत अनुमोदित क्लस्टरों का राज्य-वार और चरण-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(च) और (छ) एसएजीवाई के अंतर्गत, जनता द्वारा प्राथमिकता दी गई आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों का नियोजन किया जाता है। अतः, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट योजना की संतृप्ति की निगरानी पर बल नहीं दिया गया है।

(ज) बुलंदशहर जिले में एसएजीवाई के अंतर्गत कुल 9 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है। इन सभी 9 ग्राम पंचायतों ने अपनी वीडीपी के अंतर्गत नियोजित 100% परियोजनाओं/गतिविधियों को पूरा कर लिया है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 24.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतरांकित प्रश्न संख्या 5074 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसएजीवाई के तहत गोद लिए गए राज्य-वार ग्राम पंचायत:

राज्य	एसएजीवाई के तहत चिन्हित जीपी की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8
आंध्र प्रदेश	207
अरुणाचल प्रदेश	11
असम	46
बिहार	189
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ	115
दिल्ली	4
गोवा	14
गुजरात	238
हरियाणा	91
हिमाचल प्रदेश	45
जम्मू और कश्मीर	43
झारखंड	119
कर्नाटक	134
केरल	167
लद्दाख	4
लक्षद्वीप	2
मध्य प्रदेश	134
महाराष्ट्र	262
मणिपुर	30
मेघालय	21
मिजोरम	14
नागालैंड	6
ओडिशा	104
पुदुचेरी	10
पंजाब	65

राजस्थान	190
सिक्किम	15
तमिलनाडु	370
तेलंगाना	85
त्रिपुरा	13
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	7
उत्तर प्रदेश	553
उत्तराखंड	39
पश्चिम बंगाल	4
कुल	**3361**

एसएजीवाई के तहत चरणबद्ध गोद ली गई ग्राम पंचायतें:

चरण	एसएजीवाई के तहत चिन्हित जीपी की संख्या
चरण I (2014-16)	696
चरण II (2016-18)	468
चरण III (2018-19)	276
चरण IV (2019-20)	554
चरण V (2020-21)	381
चरण VI (2021-22)	360
चरण VII(2022-23)	333
चरण VIII (2023-24)	293
कुल	**3361**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5074 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसपीएमआरएम के तहत अनुमोदित कलस्टरों का राज्य-वार और चरण-वार विवरण:

राज्य का नाम	चरण 1	चरण 2
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1
आंध्र प्रदेश	5	6
अरुणाचल प्रदेश	1	1
असम	2	3
बिहार	4	3
छत्तीसगढ	4	6
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	1
गोवा	1	1
गुजरात	4	5
हरियाणा	6	2
हिमाचल प्रदेश	2	1
जम्मू और कश्मीर	1	1
झारखंड	3	5
कर्नाटक	3	2
केरल	4	4
लद्दाख	1	0
लक्षद्वीप	0	1
मध्य प्रदेश	7	6
महाराष्ट्र	7	5
मणिपुर	1	1
मेघालय	1	2
मिजोरम	1	1
नागालैंड	1	0
ओडिशा	5	5
पुदुचेरी	0	1
पंजाब	2	5
राजस्थान	5	6
सिक्किम	1	1

तमिलनाडु	5	3
तेलंगाना	4	3
त्रिपुरा	2	3
उत्तर प्रदेश	8	8
उत्तराखंड	2	2
पश्चिम बंगाल	7	0
कुल योग	**101**	**95**

****